न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2017

सायल	बनाम	गैर सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर		मो. इरफान पुत्र मो. इब्राहीम धोबी मुसलमान निवासी—नाई धोबी मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना—कोतवाली नागौर।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

(1) सायल की ओर से ए.पी.पी. उपस्थित।

(2) गैर सायल अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1—जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल मो. इरफान पुत्र मो. इब्राहीम निवासी नाई धोबी मोहल्ला, नागौर के विरूद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि मो. इरफान पुत्र मो. इब्राहीम धोबी मुसलमान निवासी नाई धोबी मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर क्षेत्र का आले दर्जे का जुआरी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरूद्व प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख)(i) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अतंर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2—सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से दिनांक 09-03-17 को वकील श्री सुरेन्द्र कुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दिनांक 20.04.17 को प्रस्तुत किया तथा लिखित बहस को प्रस्तुत की। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.7.15, 16.8.15 तथा 10.12.15 की फोटोप्रतियां पेश की गई।

3—सायल की ओर से बतौर शहादत श्री भंवरसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री रामरतन हैड कानि. 98, कालूराम निलम्बित स.उ.नि. तथा विनोद कुमार हैड कानि. नं. 761 के बयान कलमबद्ध करवाये गये।

4—सहायक लोक अभियोजक एवं गैर सायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का दोहराया तथा कथन किया कि मो. इरफान पुत्र मो. इब्राहीम धोबी मुसलमान निवासी नाई धोबी मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर का निवासी है। जो जुआ सट्टा की खाईवाली करते

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

बार–बार दस्तायाब किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये है, गैर सायल जुआ सट्टे करने का अभ्यस्त है तथा वर्ष 2015 में जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहता आया है। इसका नागौर व आस पास के इलाकों में दशहत व आतंक फैलाया हुआ है। उक्त गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना एवं निवासरत रहना उचित नहीं है। गैर सायल मो. इरफान पुत्र मो. इब्राहीम उम्र 22 वर्ष जाति धोबी मुसलमान निवासी नाई धोबी मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर का कृत्य धारा 2(ख)(i) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

5–वकील गैरसायल द्वारा कथन किया गया कि इस्तगासा प्रस्तुत करने के पश्चात दौराने जांच व विचारण किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई कि जिससे यह जाहिर हो कि गैरसायल अपराधी हो। इस्तगासे में पुलिस द्वारा जिन मुकदमों का जिक्र किया गया। उनको प्रदर्शित नही करवाया गया है। जिससे गैरसायल को दोषसिद्ध नही माना जा सकता। ऐसी कार्यवाही से छ माह तक के पूर्व के मुकदमे हो तो ही की जा सकती है। लेकिन गैरसायल के विरूद्व मुकदमें वर्ष 2015 व जनवरी 2016 के यानि एक वर्ष से अधिक पुराने है। जिससे उक्त मुकदमों की आड में ऐसी कार्यवाही की जाना कतेई विधिसम्मत नही है।

6–बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज. गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है, जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है–

2 (ख) ''गुण्डा'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो :–

1. या तो स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 के अध्याय 16, अध्याय 17 अध्याय 22 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 290 से 294 के अधीन दण्डनीय अपराधों का कमीशन अभ्यासतः कारित करता है, या कारित करने का प्रयास करता हे या दुष्प्रेरण करता है; अथवा
2. महिलाओं और लड़कियां के अनैतिक व्यवसाय का उन्मूलन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्याक 104) के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक –11) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
4. अफीम अधिनियम 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
5. राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्याक 48) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
6. महिलाओं या लड़किया को अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या छेड़ता हुआ पाया गया हो; अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभित्रासित करने का अभ्यासी पाया गया हो; अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या जो उनो या अन्य के अवैध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी दो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति कां संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो।

7—पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन से मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ कि गैर सायल आदतन जुआरी प्रतीत होता है। जो धारा 2(ख)(5) के अनुसार 3 बार दोष सिद्व किया जा चुका है तथा अपने अवैध आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति को सत्रांश, खतरा या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अभ्यासित अपराधी होने से राज. गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैर सायल के उक्त कृत्यों से कस्बा नागौर व आस—पास के क्षेत्र में दहशत व आंतक फैला हुआ है। अतः गैर सायल का जिला नागौर में स्वच्छन्द विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं होने से इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही उचित है।

<u>आदेश</u>

मो. इरफान पुत्र मो. इब्राहीम उम्र 22 वर्ष, जाति धोबी मुसलमान निवासी नाई धोबी मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं जिला जोधपुर के मंडोर थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा सूचना इस न्यायालय को देवें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर/ जोधपुर को भिजवाई जावे।

7—निर्णय आज दिनांकः 28-03-2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)